E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 2, Issue- 4 | April 2025

कोविड-19 के दौरान घरेलू आय और व्यय: आर्थिक स्थिरता की परीक्षा

श्रीमती भारती [1], डॉ. दिव्या दुबे [2]

[1] शोधार्थी, करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, अकलंक कॉलेज, कोटा

सारांश

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे लाखों परिवारों की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ गई। इस शोध पत्र में महामारी से पहले और उसके दौरान घरेलू आय और व्यय में हुए परिवर्तनों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के 1600 परिवारों के आंकड़ों पर आधारित है। सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके, यह शोध प्रदर्शित करता है कि महामारी के दौरान परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रबंधित किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और किस हद तक वे आर्थिक रूप से पुनः संगठित हो पाए।

सूचक शब्द: *कोविड-19, घरेलू आय, घरेलू व्यय, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता*

1. परिचय

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया। लॉकडाउन और प्रतिबंधात्मक उपायों ने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया, जिससे व्यवसायों और परिवारों की वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह शोध घरेलू आय और व्यय में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, ताकि महामारी के दौरान परिवारों की आर्थिक चुनौतियों और उनकी रणनीतियों को समझा जा सके। महामारी के दौरान कई परिवारों की आय में भारी कमी आई। नौकरियों का नुकसान, वेतन कटौती और व्यवसायों की बंदी ने आय के स्रोतों को सीमित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, परिवारों ने अपने व्यय में कटौती की, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे मनोरंजन, यात्रा और विलासिता पर। कई परिवारों ने बचत का उपयोग किया या कर्ज लिया ताकि आवश्यक खर्च जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा कर सकें।

इस संकट से निपटने के लिए परिवारों ने विभिन्न रणनीतियाँ अपनाईं। कुछ ने अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशे, जैसे ऑनलाइन काम या छोटे व्यवसाय शुरू किए। अन्य ने सरकारी सहायता योजनाओं, जैसे नकद हस्तांतरण या सब्सिडी, का लाभ उठाया। इसके अलावा, बजट प्रबंधन और वित्तीय योजना पर अधिक ध्यान दिया गया। यह शोध दर्शाता है कि कोविड-19 ने परिवारों की आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन उनकी अनुकूलन क्षमता और लचीलापन भी उजागर हुआ। भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर वित्तीय नीतियों और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

2. साहित्य समीक्षा

रे, राजन (1980) ने अपने अध्ययन में कहा कि हाउस होल्ड का अर्थमितीय स्टूडियो व्यय और मूल्य लोच के अनुमानों के साथ सरकारी नीति के निर्माण में व्यय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसलिए कई योजना मॉडल में उपयोगी साबित होता है। हालांकि अनुभवजन्य साहित्य काफी बड़ा है, अपेक्षाकृत कुछ अध्ययनों ने इसका विश्लेषण किया है बजट डेटा की समय श्रृंखला का उपयोग करके घरेलू मांग पर कुल व्यय, मूल्य और परिवार के आकार का एक साथ प्रभाव।

बेनर्जी (2004) भारत में राजस्थान राज्य के एक गरीब ग्रामीण क्षेत्र में हाल के एक सर्वेक्षण पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट में। लेखकों का इरादा स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालने का था, जहां स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनिक और निजी प्रावधान पर डेटा एकत्र करने के लिए इंटरलॉकिंग सर्वेक्षणों के एक सेट का उपयोग करने का प्रयास किया गया था।

जोशी और सिंह (2013) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में आदिवासी अपने दैनिक भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व लेने में विफल रहते हैं। उदयपुर के भीलों द्वारा आबादी वाले दो आदिवासी गांवों के एक नमूना अध्ययन से पता चलता है कि वे ज्यादातर घर में उगाए गए भोजन पर निर्भर हैं जिनमें केवल कार्बोहाइड्रेट होते हैं।

अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि कोविड-19 महामारी ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया। महामारी के दौरान निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की आय में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि हुई। राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों में किए गए अध्ययन के अनुसार, महामारी के दौरान किराना एवं राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन खर्चों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ।

3. शोध पद्धति

यह अध्ययन 1600 परिवारों पर आधारित है, जिनका चयन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के चार जिलों (कोटा, बूंदी, बाराँ और झालावाड़) से किया गया। डेटा संग्रह के लिए प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। यह डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एकत्र किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों जैसे कि, काई-स्क्वायर परीक्षण, अनोवा और तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया, ताकि घरेलू आय और व्यय के पैटर्न में बदलावों को मापा जा सके।

4. डाटा विश्लेषण एवं परिणाम

डेटा विश्लेषण स्थानीय उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं से संबंधित किया गया है। इस खंड में दक्षिण-पूर्वी राजस्थानवासियों द्वारा कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू आय एवं व्यय आकलन पर एक विश्लेषणात्मक के क्षेत्र में की गई पहलों के बेहतर परिदृश्य को पहचानने और समझने के लिए विचार किए गए विभिन्न कारकों की परिकल्पना और तुलना के उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

इस प्रयोजन के लिए, शोधकर्ता ने निम्नलिखित उत्तरदाताओं द्वारा भरी गई एक संरचित प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक डेटा एकत्र किया है। शोधकर्ता की डेटा संग्रह रणनीति निवासियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करी गई, जहां 4 बुनियादी मापदंडों का उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार हैं:

1. COVID-19 से पहले घरेलू आय मार्च (2020)
2. COVID-19 के दौरान घरेलू आय अप्रैल 1 (2020)
3. COVID-19 से पहले घरेलू व्यय मार्च (2020)
4. COVID-19 के दौरान घरेलू व्यय अप्रैल 1 (2020)

4.1 कोविड-19 से पहले और दौरान घरेलू आय

कोविड-19 महामारी से पहले अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी। नियमित आय वाले परिवारों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई नहीं हो रही थी। हालांकि, महामारी के प्रकोप के साथ ही आय में भारी गिरावट देखी गई, जिससे लाखों परिवारों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि महामारी से पहले और बाद में घरेलू आय में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए।

4.1.1 महामारी से पहले

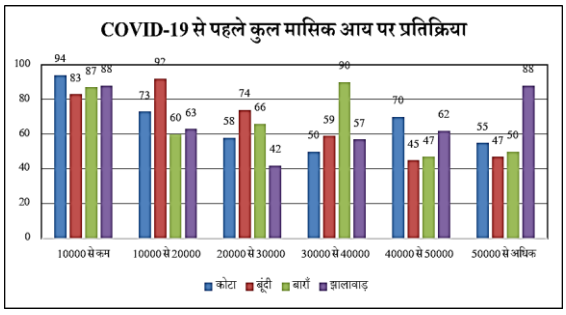

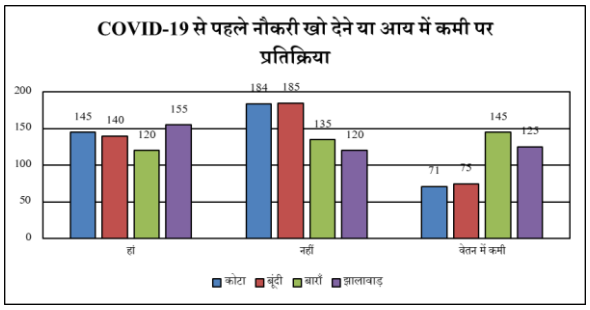

- लगभग 22% परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से कम थी। इस आय वर्ग के परिवार मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, और छोटे व्यापारी थे। उनके लिए आय के सीमित स्रोत थे, लेकिन फिर भी वे अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे।
- 18% परिवारों की मासिक आय 10,000-20,000 रुपये के बीच थी। इस श्रेणी में आने वाले लोग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, कारीगर और लघु व्यवसायी थे। इन परिवारों की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, और वे अपनी बचत पर भी ध्यान देते थे।
- 15% परिवारों की मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक थी। इस समूह में शामिल परिवार बड़े व्यापारियों, उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों और संगठित क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के थे।

4.1.2 महामारी के दौरान

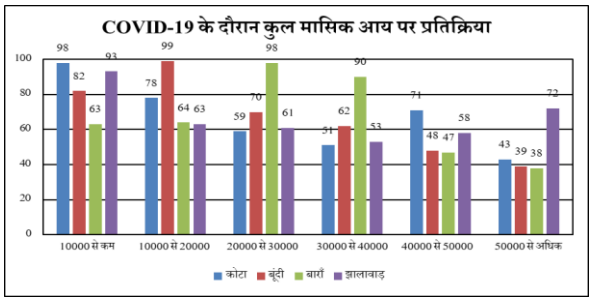

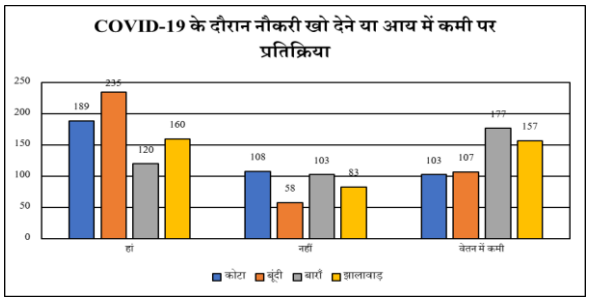

- 21% परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से कम हो गई। महामारी के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों की आय में भारी कमी आई। लॉकडाउन के कारण उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ा, जिससे उनकी आय न्यूनतम स्तर पर आ गई।
- 19% परिवारों की मासिक आय 10,000-20,000 रुपये के बीच रही। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हुई, जबकि छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को भी आर्थिक नुकसान हुआ।

- केवल 12% परिवारों की मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक बनी रही। इनमें सरकारी कर्मचारियों और बड़े व्यवसायियों का समूह शामिल था, जो अपने संसाधनों के कारण इस वित्तीय संकट से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए।

4.1.3 प्रभाव

- महामारी के कारण 51% परिवारों की आय में भारी गिरावट देखी गई।
- स्वरोजगार करने वाले और लघु व्यवसाय संचालकों को सबसे अधिक आर्थिक क्षति हुई।
- सरकारी सहायता योजनाएँ सभी जरूरतमंद परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाईं, जिससे निम्न आय वर्ग के लोग अधिक प्रभावित हुए।
- नौकरी छूटने और वेतन कटौती के कारण लाखों परिवारों को अपने खर्चों को कम करना पड़ा, जिससे उनकी जीवनशैली और उपभोक्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महामारी ने न केवल आम जनता की आय को प्रभावित किया बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया। इन परिणामों से नीति-निर्माताओं को आवश्यक नीतिगत सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन मिल सकता है।

4.2 कोविड-19 से पहले और दौरान घरेलू व्यय

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से पहले, अधिकांश परिवार अपने मासिक बजट के अनुसार संतुलित खर्च कर रहे थे। लोगों का व्यय मुख्य रूप से भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा और मनोरंजन जैसी आवश्यक और गैर-आवश्यक चीजों पर बँटा हुआ था। हालांकि, महामारी के आगमन के बाद, घरेलू व्यय के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। लॉकडाउन, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक अनिश्चितता के कारण परिवारों ने अपनी खर्च की प्राथमिकताओं को बदल दिया।

4.2.1 महामारी से पहले

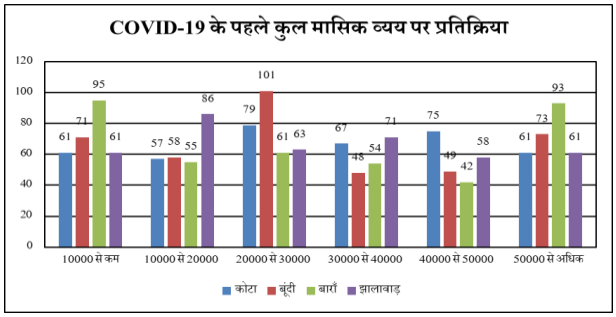

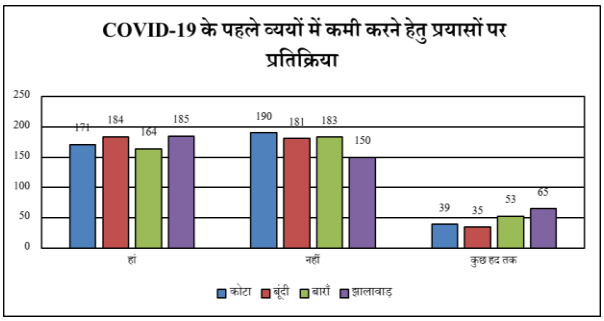

- लगभग 18% परिवारों का मासिक व्यय 10,000 रुपये से कम था। ये वे परिवार थे, जो आमतौर पर न्यूनतम आवश्यकताओं पर ही खर्च करते थे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर, निम्न-आय वाले कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग शामिल थे।
- 19% परिवारों का मासिक व्यय 20,000-30,000 रुपये के बीच था। इस आय वर्ग के लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किराए, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते थे।

- 18% परिवारों का मासिक व्यय 50,000 रुपये से अधिक था। इस समूह में उच्च वेतनभोगी कर्मचारी, व्यापारी और बड़े व्यवसायी शामिल थे, जो मनोरंजन, यात्रा और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करते थे।

4.2.2 महामारी के दौरान

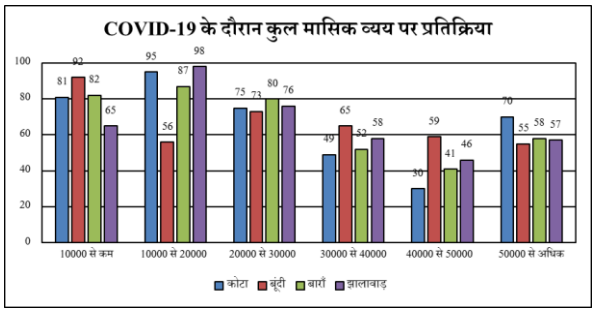

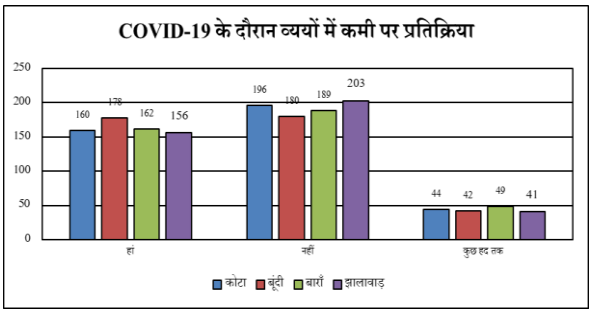

- 20% परिवारों का मासिक व्यय 10,000 रुपये से कम हो गया। महामारी के कारण इन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और वे अपने खर्चों में कटौती करने को मजबूर हो गए ।
- 21% परिवारों का मासिक व्यय 10,000-20,000 रुपये के बीच था। इस समूह ने अपनी बचत और सरकारी योजनाओं की मदद से आवश्यक वस्तुओं पर खर्च बनाए रखा, लेकिन अन्य गैर-आवश्यक खर्चों में कटौती की।
- 15% परिवारों का मासिक व्यय 50,000 रुपये से अधिक रहा। इसमें उन परिवारों की संख्या घटी जो महामारी से पहले इस व्यय श्रेणी में थे। इस समूह में मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी, उच्च-आय वाले पेशेवर और स्थिर आय वाले लोग शामिल थे।

4.2.3 प्रभाव

- 64% परिवारों ने बताया कि उनके मासिक व्यय में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से चिकित्सा खर्च, किराना और स्वच्छता उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ।
- स्वास्थ्य, किराना और स्वच्छता से संबंधित खर्चों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि परिवारों ने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
- गैर-आवश्यक वस्तुओं और विलासिता पर खर्च में भारी कमी आई। लोगों ने यात्रा, मनोरंजन, रेस्तरां और फैशन से संबंधित खर्चों को सीमित कर दिया।
- चिकित्सा आपात स्थिति के कारण कई परिवारों को कर्ज लेना पड़ा। अस्पतालों में भर्ती होने, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से कई परिवार वित्तीय संकट में आ गए।

इस अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि महामारी ने न केवल लोगों की आय को प्रभावित किया, बल्कि उनके खर्च करने की प्रवृत्ति और वित्तीय प्राथमिकताओं को भी बदल दिया। भविष्य में इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार रहने के लिए वित्तीय योजनाओं और सरकारी सहायता को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

4.3 चुनौतियाँ और बाधाएँ

कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू आय और व्यय में आए बदलावों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आईं। लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, जिससे उनके वित्तीय निर्णयों और खर्च करने की प्रवृत्ति में बदलाव आया। इस संकट के दौरान कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित थीं:

रोजगार की हानि और वेतन कटौती: महामारी के कारण लगे सख्त लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी।

डिजिटल भुगतान सेवाओं की सीमित पहुँच: ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के कई परिवार डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ रहे। इससे उन्हें सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हुई।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमान वित्तीय पुनर्बहाली: महामारी के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग रही। जहाँ शहरी क्षेत्रों में व्यवसायों और नौकरियों में कुछ तेजी से सुधार हुआ, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत धीमी गति से पुनः स्थापित हुई।

स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत: महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती लागत ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला। कई परिवारों को उधार या कर्ज लेकर अपने चिकित्सा खर्चों को पूरा करना पड़ा।

महँगाई और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें: लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएँ आईं, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इससे घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हुई और बचत दरों में गिरावट आई।

5. निष्कर्ष और सिफारिशें

कोविड-19 महामारी ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि घरेलू स्तर पर भी गंभीर वित्तीय अस्थिरता पैदा की। इस अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश परिवारों की आय में कमी आई, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर खर्च बढ़ गया। कई परिवारों को वित्तीय संकट से उबरने के लिए कर्ज लेना पड़ा, जिससे उनके दीर्घकालिक वित्तीय भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार, यह आवश्यक है कि सरकार, वित्तीय संस्थान और समाज मिलकर ऐसी नीतियाँ और योजनाएँ विकसित करें, जो भविष्य में इस तरह की आर्थिक आपदाओं से निपटने में मदद कर सकें।

5.1 नीतिगत अनुशंसाएँ

5.1.1 आर्थिक सुरक्षा योजनाएँ

- सरकार को ऐसे राहत पैकेज तैयार करने चाहिए, जो सभी आर्थिक वर्गों तक समान रूप से पहुँच सकें।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष वित्तीय सहायता कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके।

5.1.2 वित्तीय साक्षरता:

- ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, ताकि वे डिजिटल भुगतान, बैंकिंग सेवाओं और बचत योजनाओं का बेहतर उपयोग कर सकें।
- महिलाओं और कमजोर वर्गों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए माइक्रोफाइनेंस योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।

5.1.3 स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा:

- सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए।
- महामारी जैसी आपदाओं के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन स्वास्थ्य कोष बनाया जाए, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को संकट के समय वित्तीय सहायता दी जा सके।
- सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाए और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्य निर्धारण को विनियमित किया जाए।

इन अनुशंसाओं को लागू करने से भविष्य में किसी भी वैश्विक या राष्ट्रीय संकट के दौरान लोगों की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। महामारी ने हमें यह सीख दी है कि आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाना आवश्यक है, ताकि समाज के सभी वर्गों को आवश्यक सहायता मिल सके।

6 निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि कोविड-19 महामारी ने घरेलू आय और व्यय के स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो गई। महामारी के दौरान नौकरी छूटने, स्वरोजगार में गिरावट और व्यापारिक गतिविधियों के ठप होने के कारण परिवारों की आय में भारी गिरावट आई। इसके विपरीत, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता उत्पादों पर खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। महामारी के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सरकार, वित्तीय संस्थान और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की आर्थिक आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सके। सरकार को वित्तीय सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना चाहिए, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को तत्काल राहत मिल सके। इसके साथ ही, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने, वित्तीय जागरूकता अभियानों को विस्तृत करने और स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समाज के लिए एक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट से निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समावेशी और दीर्घकालिक नीतियाँ बनानी आवश्यक हैं, ताकि प्रत्येक परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ

1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। (2021)। "आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)"। उपलब्ध है: https://mospi.gov.in)
2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)। (2021)। "घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES)"। उपलब्ध है: https://mospi.gov.in)
3. राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकी संगठन। (2021)। "राज्य आय और व्यय डेटा"। उपलब्ध है: http://statistics.rajasthan.gov.in)
4. प्रायर, फ्रेडरिक एल. (1968), साम्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय, लंदन: जॉर्ज एलन और अनविन।
5. रे राजन (1980), एक समय श्रृंखला का विश्लेषण, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की समीक्षा, खंड 62, संख्या 4 (नवंबर-1980) पृष्ठ संख्या 595-602.
6. बीजी तिलक, जे (2002)। ग्रामीण भारत में शिक्षा पर घरेलू खर्च के निर्धारक।

7. जोशी और सिंह (2013), "उदयपुर (राजस्थान) के भीलों के बीच खाद्य उपभोग पैटर्न और आहार पर्याप्तता", यहां उपलब्ध है: https://pdfs.semanticscholar.org/8d0d/90c4a4003bf5155492096e4c1c5c97da0480.pdf
8. द्विवेदी, निवेदिता और द्विवेदी, अमित कुमार, ग्रामीण भारत में घरेलू व्यय पर अध्ययन: एक अनुभवजन्य साक्ष्य (26 अक्टूबर, 2016)। एसएसआरएन पर उपलब्ध: https://ssrn.com/abstract=2859292 या http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2859292.
9. हेस्मिथ, (2019). भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय के निर्धारकों की जांच: गरीबी के संदर्भ में विशेषताओं वाले परिवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन [Examination of determinants of household income in urban and rural areas of India: Assessment of different characteristics of families in the context of poverty]. (Unpublished doctoral dissertation). National Sample Survey Organization (NSSO) data (50th, 1993/1994; 55th, 1999/2000; 61st, 2004/2005; and 66th, 2009/2010).
10. कुंदु, (2019). आय के साथ घरेलू खपत में बदलाव का अध्ययन [A study of changes in household consumption patterns with income]. (Unpublished doctoral dissertation). National Sample Survey Organization (NSSO) data (68th, 66th, and 61st rounds).
11. चौधरी, पी. के. (2019)। उच्च शिक्षा पर घरेलू खर्च का पैटर्न और निर्धारक: ग्रामीण ओडिशा से साक्ष्य। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया (पृ. 165-180)। स्प्रिंगर।
12. खोलिया, तुषार, फैमिली बजट पर कोविड-19 का प्रभाव (20 नवंबर, 2020)। एसएसआरएन पर उपलब्ध है: https://ssrn.com/abstract=3885815 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3885815.
13. एबियन एंड बर्गिन, एडेल एंड रेहिल एल एंड स्वीनी ई। 2021। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और सामाजिक अनुसंधान संस्थान (ESRI), वॉल्यूम 2020 (15) के लिए COVID-19 के प्रभाव और पुनर्प्राप्ति पथ की खोज।
14. चौधरी, पी.के. और कुमार, ए. (2022)। भारत में पेशेवर उच्च शिक्षा पर परिवार कितना खर्च करते हैं? एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से परिणाम। ऋषि पत्रिकाएँ।. https://doi.org/10.1177/09737030221099880.